

प्रधानमंत्री – कैबिनेट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025–26 की रबी की फसलों के लिए फास्फोरस और पोटैश उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अन्नदाताओं को सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध होंगे, बल्कि उनकी आय भी बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री दौरा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। वह आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हितों की पैरवी करेंगे। इन मुलाकातों को राज्य की वित्तीय स्थिति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री

वर्तमान राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई प्रयास कर रही है। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा दो वर्षों में गाय के दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 51 रुपए और भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 61 रुपए प्रति लीटर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं और पांगी क्षेत्र में उगाए गए जौ को 60 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल मिल रहा है।

पहली बार हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना। दूध के मूल्य पर 51 रुपये का स्पॉट प्राइस लगाया जाता है। 2–3 साल पहले की आप बात देखिए तो दूध का मूल्य 28 व 30 रुपये हुआ करता था। 2 साल में उसे बढ़ाकर 51 रुपये कर दिया। मक्की का 40 रुपये किलो सरकार खरीदेगी। 60 रुपये किलो गेहूं सरकार खरीदेगी, हल्दी उगाई है, तो 90 रुपये किलो सरकार खरीदेगी और किसीने जौ खरीदी है तो उसे 60 रुपये किलो सरकार खरीदेगी। इस प्रकार किसानों के हाथों में हम डायरेक्ट बैनिफिट दे रहे हैं।

धारा-118 को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने सत्ता में रहते हुए प्रदेश की सम्पदा को लुटाया है।

हमें बोलते हैं कि धारा 118 को हम कमजोर कर रहे हैं। बददी में 4 बड़े कस्टमाइज पैकेज पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 हजार बीघा बिना रजिस्ट्री के एक रुपये प्रति सेक्यूर मीटर के हिसाब से दे दी। यानी एक पांच हजार बीघा मात्र 14 करोड़ रुपये में कोई पैसा न लेकर बो इंडस्ट्री के नाम पर दे दिए। उनकी कीमत तकरीबन एक हजार करोड़ रुपये थी। यह भारतीय जनता पार्टी की करतूत है।

अनिरुद्ध सिंह

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की पगोग, भोंट और डूमी पंचायतों का कल दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किये। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है।

सारथी प्रोजेक्ट

केन्द्र सरकार का सारथी प्रोजेक्ट पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चम्बा में आरंभ किया गया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉ जालम भारद्वाज ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत अब मेडिकल कालेज में स्वास्थ्य सेवाओं को ओर बेहतर बनाने के लिए स्वयंसेवक छात्र छात्राएं अपनी सेवाएं देंगे।

सुर्खियां समाचार पत्रों से

आज समाचार पत्रों ने अलग-अलग खबरों को प्रमुखता दी है।

अमर उजाला की सुर्खी है—शिक्षकों को डिमोट करने—संशोधित वरिष्ठता सूची जारी करने पर रोक—हाईकोर्ट ने सरकार सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। **दैनिक भास्कर ने हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है**—नालागढ़ की रत्ता नदी में प्रदूषण फैलाने वालों की रेगुलर मॉनिटरिंग करे पीसीबी।

दिव्य हिमाचल की खबर है—हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 22 हजार 6 सौ 53 रुपये ज्यादा। **पंजाब केसरी व आपका फैसला ने** मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी दी है—सीबीएसई स्कूल अध्यापकों का बनेगा अलग कैडर। **दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है**—वितीय मोर्चे पर सूबे को मजबूती प्रदान करने को सक्रिय सीएम सुक्खू। **दैनिक जागरण का शीर्षक है**—कमीज उतरवा कांटेदार झाड़ी से पीटा बच्चा, शिक्षिका निलंबित। मौसम पर **हिमाचल दस्तक ने लिखा है**—सूबे में पारा लुढ़कने से बढ़ा सुबह—शाम ठंड का प्रकोप।